RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 मुंबई : शनिवार 23 अगस्त 2025 वर्ष 07 अंक 125 संपादक : फैसल शेख पृष्ठ : 4 कीमत : 03 रुपये

दैनिक
रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक

मुंबई : सरकारी संस्थाओं पर 3 हजार 241 करोड़ प्रॉपर्टी टैक्स बकाया...

Page - 2

गणेश चतुर्थी से पहले गड्ढा मुक्त होगी मुंबई !

8,000 से अधिक शिकायतों पर 3 दिन में ऐसे होगा काम...

मुंबई उपनगरीय मंत्री आशीष शेलार ने अधिकारियों को गणेश चतुर्थी से पहले अगले तीन दिनों में मुंबई की सड़कों पर बने गड्ढों को भरने के निर्देश दिए हैं. इस वर्ष से गणेशोत्सव को राजकीय उत्सव के रूप में मनाया जाएगा और इसी क्रम में आशीष शेलार ने मुंबई की व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक की. इस बैठक में मुंबई नगर निगम आयुक्त भूषण गगरानी, यातायात पुलिस अधिकारी, एमएसआरडीसी अधिकारी, एमएमआरडीए, एसआरए अधिकारी, रेलवे अधिकारी और पूर्व नगरसेवक उपस्थित थे.

इस बारे में बोलते हुए आशीष शेलार ने कहा कि मुंबई में बारिश के कारण सड़कों पर बने गड्ढों ने मुंबईवासियों की चिंता बढ़ा दी है. सड़कों, राजमार्गों और आंतरिक सड़कों पर गड्ढों की शिकायतें बड़ी संख्या में मिल रही हैं और आज इस संबंध में मुंबई नगर आयुक्त, एमएसआरडीसी, एमएमआरडीए, जिला कलेक्टर, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट और अन्य संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई.

इस तकनीक से जल्दी हो पाएगा काम

अब तक नगर निगम में 8,000 से अधिक शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं. इसके अलावा कई जगहों पर गड्ढे हैं और इस बैठक में गणेश चतुर्थी से पहले अगले तीन दिनों में सभी गड्ढों को पूरी तरह से भरने के स्पष्ट निर्देश दिए गए चूंकि नगर निगम द्वारा गड्ढों को भरने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ह्यमैस्टिक तकनीक' यातायात की दृष्टि से कारगर साबित हो रही है, इसलिए आयुक्त ने क्षेत्रवार नियुक्त ठेकेदारों को इसी तकनीक का उपयोग करके काम करने के निर्देश दिए.

काम पूरा होने के बाद रिपोर्ट पेश करने के निर्देश

साथ ही, वाकोला, विक्रोली, गोरेगांव जैसे स्थानों पर फ्लाईओवर पर गड्ढों के कारण यातायात की भीड़ बढ़ रही है, इसे देखते हुए बैठक में निर्णय लिया गया कि एमएसआरडीसी तत्काल उपाय करे, अन्यथा नगर निगम स्वयं गड्ढों को भरने का काम करेगा. आज की बैठक में गणेश चतुर्थी से पहले मुंबई को गड्ढा मुक्त बनाने के उद्देश्य से सभी कार्य तुरंत पूरा करके उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए.

मछुआरे पर बलात्कार का मामला दर्ज

पालघर : अनार्ला की एक 19 वर्षीय युवती ने अनार्ला सागरी पुलिस स्टेशन में एक स्थानीय युवक के खिलाफ बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई है। युवती का आरोप है कि युवक ने शादी का झूठा वादा करके उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। पुलिस के अनुसार, जोगेश्वरी में काम करने वाली पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा है कि फरवरी और जुलाई 2025 (सटीक तारीख याद नहीं) के बीच, वसई निवासी 19 वर्षीय मछुआरे, आरोपी ने उसे कलंब बीच के पास एक कमरे में ले जाया।

मुंबई में हुआ 60.82 करोड़ की ठगी रैकेट का भंडाफोड़ !

मुंबई : शहर में बढ़ते साइबर धोखाधड़ी के मामलों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, मुंबई पुलिस ने एक साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ किया है और 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक दंपति भी शामिल है, जिन्होंने कथित तौर पर देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों से 60.82 करोड़ रुपये की ठगी की थी, एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारी ने बताया कि हाल ही में गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से पाँच ने कथित तौर पर अपने बैंक खाते और सिम कार्ड बेचे थे, जिनका इस्तेमाल साइबर धोखाधड़ी के लिए किया गया था. रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस उपायुक्त (जांच) राज तिलक रोशन ने घटना के बारे में बात करते हुए कहा, ''ये गिरफ्तारियाँ 12 अगस्त को पश्चिमी उपनगर कांदिवली में एक कार्यालय पर मुंबई अपराध शाखा के छापे के बाद की गईं, जिसमें अधिकारियों ने सिम कार्ड और बैंक पासबुक जब्त किए. '' उन्होंने आगे कहा, ''गिरोह ने 943 बैंक खाते खरीदे थे, जिनमें से 180 का इस्तेमाल धोखाधड़ी के लिए किया गया था,'' और कहा कि आरोपी पिछले साल से इस तरीके का इस्तेमाल कर रहे थे. पुलिस उपायुक्त ने आगे बताया, ''अभियान के बाद, 12 अगस्त को पाँच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और बाकी को जाँच के दौरान गिरफ्तार किया गया.'' अधिकारी ने घटना पर प्रकाश डालते हुए यह भी बताया कि गिरोह ने 7,000-8,000 रुपये में सिम कार्ड और बैंक खाते खरीदे और उनका इस्तेमाल डिजिटल अरेस्ट स्कैम, ऑनलाइन शॉपिंग और शेयर ट्रेडिंग धोखाधड़ी के लिए किया. मुंबई पुलिस

मुंबई : अटल सेतु पर इलेक्ट्रिक वाहनों को टोल टैक्स से छूट

मुंबई : मुंबई और नवी मुंबई के बीच यात्रा करने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने घोषणा की है कि अब अटल सेतु पर चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों से कोई टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा। यह कदम शहरवासियों को आर्थिक लाभ के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देगा।

अटल सेतु, जिसे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक कहा जाता है, 21.8 किलोमीटर लंबा पुल है। यह पुल मुंबई के सेवड़ी इलाके को नवी मुंबई के न्हावा शेवा से जोड़ता है। इस पुल के शुरू होने से यात्रा का समय लगभग दो घंटे से घटकर सिर्फ 20 मिनट रह गया है।

पहले इस पुल पर यात्रा करने वाले वाहनों को भारी टोल टैक्स देना पड़ता था। अब इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को यह छूट मिलने से उनकी जेब पर बोझ कम होगा। सरकार का उद्देश्य लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और शहर में स्वच्छ परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देना है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला न केवल यात्रियों के लिए राहत है, बल्कि वायु प्रदूषण को कम करने और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब मुंबई और नवी मुंबई के बीच सफर तेज, सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल बन गया है।

जुए के अड्डे पर मंत्री नितेश राणे की छापेमारी, कंकावली बाजार में हंगामा

मुंबई : कंकावली बाजार में मंत्री नितेश राणे ने मटका जुए के अड्डे पर धावा बोला। 9-10 लोग गिरफ्तार किए गए। पुलिस भी मौके पर पहुँच गई और जांच जारी है। राणे ने कहा कि इलाके में मटका जुआ बड़े पैमाने पर चल रहा था और इसमें एक बड़ा किंग शामिल था। उन्होंने बताया कि संरक्षक मंत्री बनने के बाद से ही वे पुलिस को बार-बार कार्रवाई के निर्देश देते आ रहे हैं। मंत्री राणे का खुद जुए के अड्डे पर धावा मारना और जुआड़ियों का पकड़ा जाना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करती है। जरूरी सवाल है कि मंत्री को जुए के अड्डे के बारे में पता है, लेकिन पुलिस की आंख बंद है।

संपादकीय...

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

केंद्र 'पुलिस स्टेशन' नहीं...

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने संविधान के 130वें संशोधन वाले विधेयक लोकसभा में पेश किए। उनमें गंभीर और विवादास्पद प्रावधान किए गए हैं। दरअसल संविधान का बुनियादी सिद्धांत है कि जब तक किसी आरोपित को अदालत अपराधी या दोषी करार न दे, तब तक आरोपित व्यक्ति 'मासूम' है, 'निर्दोष' है, लेकिन प्रस्तावित बिल का विषय है कि कोई प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य सरकार का मंत्री 30 दिन हिरासत में रहता है, तो 31वें दिन वह संवैधानिक पद के 'अयोग्य' हो जाएगा। उसे इस्तीफा देना पड़ेगा अथवा बर्खास्त कर दिया जाएगा। इन प्रावधानों को विपक्ष ने संविधान-विरोधी, न्याय-विरोधी और मौलिक अधिकार-विरोधी करार दिया है, लिहाजा कुछ विपक्षी सांसदों ने बिल की प्रतियां फाड़ी हैं और उन्हें सत्ता पक्ष की तरफ फेंका है। इसे 'राक्षसी बिल' भी करार दिया गया है। गृहमंत्री की दलील है कि यह बिल सरकार और राजनीति में नैतिकता और शुद्धिकरण के मद्देनजर लाया गया है। यह अर्द्धसत्य है, क्योंकि भाजपा में ऐसे कई नेता शामिल किए गए, जिन पर गंभीर आपराधिक मामले चल रहे थे, लेकिन बाद में एजेंसियों ने उन्हें धूमिल कर दिया। ऐसे नेता मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक हैं। बहरहाल संसद में हंगामे और विरोध को देखते हुए संविधान संशोधन बिल संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजने की घोषणा की गई। समिति में 21 सांसद लोकसभा और 10 सांसद राज्यसभा के होंगे। बेशक अधिक सांसद सत्ता पक्ष के होंगे, लिहाजा बुनियादी बिल में ज्यादा संशोधनों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जेपीसी को संसद के शीत सत्र के पहले दिन तक रपट सौंपने को कहा गया है। विषय का विश्लेषण करने से पूर्व एडीआर की रपट गौरतलब है कि 2024 के संसदीय चुनाव में जो सांसद लोकसभा के लिए चुने गए थे, उनमें से करीब 46 फीसदी पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2009 में यह औसत 30 फीसदी था। सर्वोच्च अदालत के 'न्यायालय मित्र' ने उसे बताया है कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ करीब 5000 आपराधिक मामले अब भी लंबित हैं। इस डाटा के मद्देनजर भी ऐसा संविधान संशोधन बिल संसद में पेश करना अपेक्षित और स्वीकार्य नहीं है। दरअसल केंद्र और राज्य सरकारों की अलग-अलग भूमिकाएं संविधान में तय की गई हैं।

उनके अधिकार भी तय किए गए हैं। संघीय ढांचे पर आघात नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार 'पुलिस स्टेशन' की भूमिका में नहीं आ सकती। संभव है कि बिल बनाते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल का उदाहरण केंद्र सरकार और अधिकारियों के मानस में रहा होगा! केजरीवाल को 177 दिन तक जेल में रखा गया। उनके खिलाफ न तो आरोप अदालत में तय हुए और न ही किसी अदालत ने उन्हें 'दोषी' करार दिया। ऐसे कानूनों में संशोधन किया जाना चाहिए।

Rokthok Lekhani News Update
WhatsApp group

editor@rokthoklekhani.com
+91 9987775650
Faisal Shaikh @faisalrokthok

ROKTHOK LEKHANI NEWS
KHABREIN BE ROKTOK
Watch Us On YouTube
LIKE SHARE COMMENT SUBSCRIBE
youtube@rokthoklekhani

मुंबई : सरकारी संस्थाओं पर 3 हजार 241 करोड़ प्रॉपर्टी टैक्स बकाया...

मुंबई : मनपा प्रशासन प्रॉपर्टी टैक्स बकाएदारों से बकाया संपत्ति कर वसूलने के लिए जूझ रही है। बकाएदारों में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उनसे जुड़े विभिन्न प्राधिकरण शामिल है। मनपा प्रशासन का इन सभी से कुल 3 हजार 241 करोड़ रुपए बकाया बना हुआ है। इनमें सबसे अधिक 1,601 करोड़ 77 लाख रुपए संपत्ति कर एमएमआरडीए से अभी तक नहीं मिला है। मुंबई में किसी आम नागरिक का प्रॉपर्टी टैक्स में बकाया होने पर मनपा प्रशासन बकाएदार की प्रॉपर्टी सील कर नीलाम तक कर देती है। मनपा का विभिन्न सरकारी संस्थाओ पर हजार करोड़ का बकाया होने के बावजूद उसकी वसूली करने के मनपा को नाको चने चबाने पड़ रहे है, लेकिन इसके बावजूद मनपा को कोई पैसा नहीं मिल पा रहा है। मनपा का बकाया केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एमएमआरडीए, म्हाडा और पुलिस आयुक्तालय पर करोडो का बकाया बना हुआ है।

मनपा के कुल बकाया 3,241 करोड़ रुपए हैं। इसमें सबसे ज्यादा बकाया एमएमआरडीए पर 1,601 करोड़ 77 लाख रुपए है। म्हाडा पर 612 करोड़ 41 लाख, केंद्र सरकार पर 423 करोड़ 24 लाख, राज्य सरकार पर 424 करोड़ 36 लाख, पुलिस आयुक्तालय पर 119 करोड़ 46 लाख जबकि बीपीटी, मध्य और पश्चिम रेलवे पर भी करोड़ों रुपए बकाया हैं। मनपा नियमों के अनुसार संपत्ति कर 90 दिनों के भीतर जमा करना आवश्यक है। ऐसा न करने पर पहले 'डिमांड लेटर', फिर 21 दिन की अंतिम नोटिस दी जाती है। इसके बावजूद पिछले 10-15 सालों में बकायेदारों की सूची कम नहीं हुई है। एमएमआरडीए ने मेट्रो परियोजनाओं के लिए दी गई जमीनों पर बकाया टैक्स माफ करने की मांग की है वहीं म्हाडा ने भी पुनर्विकास परियोजनाओं पर कुछ टैक्स माफ करने का पत्र भेजा है। फिलहाल समय पर टैक्स न भरने पर 2% अतिरिक्त दंड लगाया जाता है। इसे अधिक मानते हुए दंड को 1% करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास लंबित है। 25 वार्डों में शीर्ष बकाएदारों की संपत्तियों की जल्द होगी नीलामी मुंबई के 25 वार्डों के सबसे बड़े बकायेदारों की सूची तैयार की जा रही है। इन 25 वार्डों में से 22 वार्डों के बकायेदारों की सूची तैयार कर उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई है। अब नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

नालासोपारा : 40 वर्षीय व्यक्ति का शव तैरता हुआ मिला

नालासोपारा : नालासोपारा (पश्चिम) के हनुमान नगर इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब एक नाले में 40 वर्षीय व्यक्ति का शव तैरता हुआ मिला। मृतक की पहचान रमेश तिवारी के रूप में हुई है, जो नालासोपारा (पूर्व) में रहते थे और एक निजी संस्थान में सुरक्षा गार्ड के तौर पर काम करते थे। सबसे पहले स्थानीय लोगों ने शव को देखा और तुरंत इसकी जानकारी पूर्व सभापति अतुल सालुंके को दी। सालुंके ने बिना देरी किए पुलिस और दमकल विभाग को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जेसीबी की मदद से शव को नाले से बाहर निकाला। इसी दौरान, रमेश तिवारी की पत्नी उन्हें ढूंढते हुए घटनास्थल पर पहुंचीं और उन्होंने शव की पहचान अपने पति के रूप में की। उन्होंने बताया कि रमेश रोज सुबह 10 बजे तक घर लौट आते थे, लेकिन आज देर होने की वजह से वह उनकी तलाश में निकली थीं।

मुंबई: 3.23 करोड़ रुपये का धोखाधड़ी!

7 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज

मुंबई : पार्कसाइट पुलिस ने 7 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कंपनी का आरोप है कि इन व्यक्तियों ने स्टील सामान का 3.23 करोड़ रुपये का धोखाधड़ी किया। ऋक्क्ष्फमें नामजद आरोपीः ऋक्ष्फ में दीपक राठौड़ (के. दिव्या इंडस्ट्रियल प्रा. लि.), करण सोनेरी (डी.के. एंटरप्राइजेज), दीप पटेल और मेहुल भट्ट (सिल्वर स्पैन फैब प्रा. लि.), तथा हितेश पंचाल और उनकी पत्नी रुतुजा पंचाल (श्री मनीभद्र फैब्रिकेटर्स) के नाम शामिल हैं। वहीं, हितेश पंचाल ए.डी. एंटरप्राइजेज के भी मालिक हैं। पुलिस ने बताया कि मामला स्टील की सप्लाई और भुगतान को लेकर है। शीटल एंटरप्राइजेज ने शिकायत की कि आरोपी कंपनियों ने स्टील सामग्री की डिलीवरी के नाम पर कंपनी को धोखा दिया। आरोपियों ने माल प्राप्त करने के बाद भुगतान नहीं किया, जिससे कंपनी को भारी आर्थिक नुकसान हुआ।

पुलिस ने कहा कि FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और मामले में संबंधित कंपनियों और आरोपियों से विवरण मांगा जा रहा है। ''हम शीघ्र ही पूरे मामले की जांच कर आरोपियों को न्याय के दायरे में लाएंगे,'' पुलिस अधिकारी ने बताया। आर्थिक धोखाधड़ी के इस मामले में यह कदम व्यापारिक जगत में सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयास के तहत उठाया गया है। शीटल एंटरप्राइजेज ने कहा कि वह आरोपियों से नुकसान की वसूली के लिए कड़ी कार्रवाई की उम्मीद करती है। इस मामले ने मुंबई के व्यापारिक क्षेत्र में स्टील व्यापार में बढ़ती धोखाधड़ी की चिंता को भी बढ़ा दिया है। व्यापारियों ने कहा कि उन्हें इस तरह की धोखाधड़ी से बचाव के लिए मजबूत निगरानी और कानूनी कार्रवाई की जरूरत है।

मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को धमकी भरा ईमेल...

मुंबईः 20 अगस्त को मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को मकी भरा ईमेल मिला। यह ईमेल पहले वॉर्ली के फोर सीजन्स होटल को भेजा गया था और इसमें कहा गया कि ''7 फ्ळ क्ए्ळ ब्लास्ट झ्र रिट्ज कार्लटन सिंगापुर, फोर सीजन्स मुंबई के 3 श्क्ढ कमरे जल्द खाली करें।''ईमेल में यह भी मांग की गई कि तमिलनाडु पुलिस को यूनियन बनाने की अनुमति दी जाए। प्रोटोकॉल के अनुसार, अधिकारियों ने तुरंत संबंधित सभी विभागों को सूचित किया। साइबर पुलिस फिलहाल ईमेल भेजने वाले की पहचान कर रही है।

यह धमकी मुंबई में पहले आए अन्य सुरक्षा खतरों के कुछ दिन बाद आई है। 14 अगस्त को मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को एक धमकी भरी कॉल मिली थी, जिसमें कहा गया कि किसी ट्रेन में बड़ा बम विस्फोट होगा। कॉल अचानक समाप्त हो गई और जब पुलिस ने कॉल वापस करने की कोशिश की, तो नंबर बंद पाया गया। उस घटना के बाद मुंबई पुलिस ने रेलवे पुलिस को सूचित किया और रेलवे स्टेशनों तथा भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जांच की। हालांकि किसी संदिग्ध वस्तु का पता नहीं चला।

मुंबई पुलिस ने कहा कि ऐसे मामलों में तुरंत सतर्कता बरतना और सभी सुरक्षा उपाय अपनाना आवश्यक है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे सार्वजनिक स्थलों और होटल परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। साइबर और आतंक विरोधी टीमों ने ईमेल और कॉल की जांच शुरू कर दी है, ताकि धमकी देने वालों को पकड़कर उचित कार्रवाई की जा सके। सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि मुंबई में किसी भी प्रकार के खतरों को गंभीरता से लिया जा रहा है और सभी प्रमुख होटल और भीड़-भाड़ वाले स्थानों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

नवी मुंबई : तस्करी विरोधी अभियान के दौरान 42 संरक्षित मुनिया पक्षियों को बचाया; दो तस्कर गिरफ्तार

नवी मुंबई : पनवेल के उल्वे नोड में वन विभाग ने तस्करी विरोधी अभियान के दौरान कुल 42 संरक्षित मुनिया पक्षियों को बचाया। वन्यजीव कल्याण संघ की मदद से की गई छापेमारी में दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया। जब्त किए गए पक्षियों में 16 स्केली-ब्रेस्टेड मुनिया, 14 तिरंगा मुनिया और 12 लाल मुनिया शामिल हैं। अधिकारियों ने पुष्टि की कि पक्षियों को अवैध बिक्री के लिए रखा जा रहा था। यह छापेमारी उल्वे के सेक्टर 8 में एक पालतू जानवरों की दुकान पर की गई, जहां पक्षियों को अवैध रूप से बेचा जा रहा था। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कोपरखैराने निवासी देवेंद्र लालचंद पाटिल और पेन निवासी हरेश दामोदर पाटिल के रूप में हुई है। दोनों पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (धारा 9, 39, 48 (ए), 51) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

नवी मुंबई : मोरबे बांध 1999 में चालू होने के बाद से जलाशय की गाद नहीं निकाली गई

नवी मुंबई : नगर निगम (एनएमएमसी) ने मोरबे बांध में 100% जल प्रवाह का दावा किया है, लेकिन एक आरटीआई के जवाब से पता चला है कि 1999 में इसके चालू होने के बाद से जलाशय की गाद नहीं निकाली गई है। नगर निगम का कहना है कि पहाड़ों से घिरा होने के कारण बांध में गाद जमा नहीं होती, लेकिन पर्यावरणविदों ने चेतावनी दी है कि गाद निकालने की अनदेखी शहर को संकट में डाल सकती है। एनएमएमसी के एक अधिकारी ने कहा, ''मोरबे में गाद जमा नहीं है और उसे गाद निकालने की जरूरत नहीं है। गाद निकालने के दावे और बांध की क्षमता के बीच कोई संबंध नहीं है। बांध में मौजूद पानी अगले एक साल तक शहर के लिए पर्याप्त होगा।''

मुंबई : मीठी नदी गाद निकासी घोटाले में तीसरी गिरफ्तारी...

मुंबई : मीठी नदी गाद निकासी में 65 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच में उस समय एक बड़ी सफलता मिली जब मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने गुरुवार सुबह बोरीवली के एक ठेकेदार शेरसिंह राठौड़ को गिरफ्तार कर लिया। बाद में राठौड़ को एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। मीठी नदी गाद निकासी घोटाले में यह तीसरी गिरफ्तारी है। अधिकारियों के अनुसार राठौड़ कथित तौर पर नदी की गाद निकासी के काम में बढ़ा-चढ़ाकर बिल बनाने और अन्य अनियमितताओं में शामिल था। इस घोटाले में कथित तौर पर कई ठेकेदार और नगर निगम के अधिकारी शामिल हैं। ईओडब्ल्यू द्वारा वित्तीय सुरागों का पता लगाने और गबन की गई धनराशि के लाभार्थियों की पहचान करने के लिए जाँच की जा रही है। सूत्रों ने कहा कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां होने की संभावना है।

ठाणे : ठाणे में केंद्रीय जीएसटी विभाग ने कर चोरी का एक बड़ा मामला उजागर ; व्यापारी गिरफ्तार

ठाणे : ठाणे में केंद्रीय जीएसटी विभाग ने कर चोरी का एक बड़ा मामला उजागर किया है, जिसमें 47.32 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट की फजीर्वाड़ा सामने आया है। इस कार्रवाई में विभाग ने मुख्य आरोपी विवेक राजेश मौर्य को गिरफ्तार किया है, जो अपनी फर्म M/s KSM E»»fterprises के जरिए यह घोटाला कर रहा था। जांच में सामने आया कि आरोपी ने फर्जी कंपनियां बनाकर और कागजातों का इस्तेमाल कर, बिना किसी वस्तु या सेवा की आपूर्ति किए करोड़ों रुपये का ITC क्लेम किया।

नवी मुंबई : खाली डीजल परिवहन टैंकर से धुआँ, टल गया हादसा...!

नवी मुंबई : सीबीडी बेलापुर फ्लाईओवर पर पनवेल की ओर एक बड़ा हादसा टल गया जब एचपीसीएल के एक खाली डीजल परिवहन टैंकर से धुआँ निकलता देखा गया। इस घटना को सबसे पहले कार्यकर्ता सुदीप घोलप ने देखा। वह शाम लगभग 6:45 बजे रास्ते में थे और उन्होंने सीबीडी ट्रैफिक पुलिस और नवी मुंबई नगर निगम (एनएमएमसी) की फायर ब्रिगेड को सूचित किया। घोलप ने कहा, ''मैं अपने काम पर जा रहा था जब मैंने वाहन से धुआँ निकलते देखा। दोनों एजेंसियां तुरंत मौके पर पहुँचीं।'' फायर ब्रिगेड ने आग के खतरे को कम करने के लिए टैंकर पर पानी का छिड़काव किया, जबकि सीबीडी ट्रैफिक पुलिस ने घटना के कारण हुए यातायात जाम को संभाला और मार्ग को साफ किया।

बढ़ते शहरी निर्माण के बीच पार्किंग संकट गहरा...

सिटी प्रशासन कार्रवाई में सक्रिय

नागपुर : शहर तेजी से बदल रहा है लेकिन शहर की बुनियादी समस्या, यानी पार्किंग की जगह, अभी भी जस की तस बनी हुई है। शहर की सड़कें खासकर प्रमुख वाणिज्यिक क्षेत्रों – सीताबुलडी, रामदासपेट और धांतोली – में पार्किंग के लिए उपलब्ध मुक्त स्थान तेजी से घट रहा है। प्रशासन लगातार 'नो पार्किंग' उल्लंघन के नाम पर कार्रवाई करता है, जबकि अधिकतर स्थान पर आधिकारिक पार्किंग की सुविधा या तो मौजूद नहीं है या अवैध निर्माण के चलते बाधित है। ऐसे में आम वाहन मालिकों को बिना किसी गलती के जुमार्ना या कार्रवाई झेलनी पड़ती है। शहर में सक्रिय और संगठित नागरिक दबाव समूहों की कमी के कारण यह समस्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। नागरिक बार-बार दबाव में रह रहे हैं, जबकि ऊंची और ग्लास-पैनल वाली नई इमारतें शहर को आधुनिक और शानदार दिखाती हैं, सड़क पर स्थित वास्तविक स्थिति इसके विपरीत है।

स्थानीय प्रशासन द्वारा पार्किंग समस्या के स्थायी समाधान के लिए ठोस प्रयास नहीं किए जाने से स्थिति और भी जटिल हो गई है। सड़कों पर पार्किंग की कमी और 'नो पार्किंग' नियमों के क्रियान्वयन के कारण वाहन मालिकों और आम नागरिकों में असंतोष बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि नगर नियोजन और पार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान न देने से वाणिज्यिक क्षेत्र में ट्रैफिक जाम और रोड सेफ्टी समस्याएं बढ़ेंगी। प्रशासन को जरूरी है कि शहर में पर्याप्त पार्किंग स्थान विकसित करे और नागरिकों के लिए संतुलित नियम बनाएं। साथ ही, यह भी जरूरी है कि शहर में नागरिक समूह सक्रिय हों और पार्किंग जैसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाएं। शहर की शहरी विकास योजना में पार्किंग और सड़क उपयोग का संतुलित प्रबंधन प्राथमिकता के रूप में होना चाहिए, ताकि नागपुर के नागरिकों को रोजमर्रा की परेशानी से राहत मिल सके।

ठाणे : घोड़बंदर मार्ग पर जाम से मिलेगी राहत...

भारी वाहनों पर सुबह 6 से रात 12 बजे तक रोक...

ठाणे : घोड़बंदर मार्ग पर बढ़ती यातायात कोंडी को कम करने के लिए अब सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक भारी मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि यदि इस वाहतूक को भिवंडी मार्ग की ओर मोड़ा गया तो आम वाहनचालकों को निश्चित रूप से बड़ी राहत मिलेगी। वे ठाणे महापालिका सभागृह में आयोजित शहर के विकास कार्यों की प्रगति समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। बैठक में आयुक्त सौरभ राव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

सरनाईक ने बताया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के मार्गदर्शन में ठाणे महापालिका क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए लगभग 1800 करोड़ रुपए का निधि मंजूर हुआ है। इस राशि से शुरू किए गए अधिकांश कार्यों का लोकार्पण 15 अक्तूबर तक करने का लक्ष्य है। उन्होंने निर्देश दिया कि 31 दिसंबर तक घोड़बंदर मार्ग पर सेवा सड़कें जोड़ दी जाएं और मध्यवर्ती खुली जगहों का सीमेंटकरण कर उन्हें मुख्य मार्ग से जोड़ा जाए, ताकि नागरिकों की यातायात समस्या दूर हो। बैठक में मंत्री ने नांगला बंदर खाड़ी तट के विकास के दौरान बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर वन क्षेत्र बढ़ाने का आ''ान किया। शहर में बढ़ती आवारा कुत्तों की समस्या को देखते हुए उन्होंने ठाणे शहर के बाहर श्वान पुनर्वसन केंद्र स्थापित करने का भी सुझाव दिया। शहर की भावी यातायात जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरनाईक ने पॉड टैक्सी प्रकल्प का उल्लेख किया।

पालघर : दवा कंपनी में नाइट्रोजन गैस का रिसाव... चार कर्मियों की मौत!

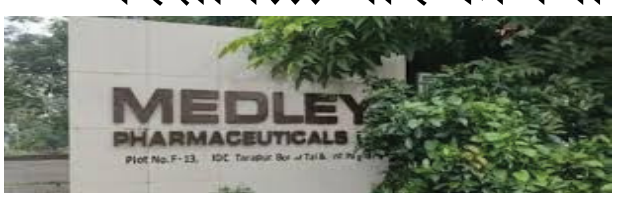

पालघर : महाराष्ट्र के पालघर जिले के तारापुर एमआईडीसी में स्थित एक दवा कंपनी में नाइट्रोजन गैस का रिसाव होने से कम से कम चार कर्मियों की मौत हो गई। दो अन्य कर्मी गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह घटना बोईसर के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित 'मेडले फार्मा' में दोपहर को हुई। बोईसर मुंबई से करीब 130 किलोमीटर दूर है। पालघर जिला आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख विवेकानंद कदम ने कहा कि अपराह्न ढाई से तीन बजे के बीच कंपनी की एक इकाई में नाइट्रोजन गैस का रिसाव हुआ जिससे वहां काम कर रहे कर्मचारी प्रभावित हुए।

उन्होंने बताया, ''छह कर्मियों को अस्पताल ले जाया गया जहां शाम को चार कर्मियों की मौत हो गई।'' कदम ने कहा कि दो अन्य को एक स्थानीय अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों ने बताया कि मृतकों की पहचान कल्पेश राउत, बंगाली ठाकुर, धीरज प्रजापति और कमलेश यादव के रूप में हुई है, जबकि रोहन शिंदे और नीलेश हडाल का इलाज किया जा रहा है।

मुंबई : मनपा एस वार्ड ने पवई के त्रिबोलि बिल्डिंग के सामने बनी झोपड़पट्टियों को जमिदोज कर दिया...

मुंबई : मनपा एस वार्ड ने बारिश रुकते ही पवई के त्रिबोलि बिल्डिंग के सामने बनी झोपड़पट्टियों को जमिदोज कर दिया। मनपा की कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों द्वारा भरी विरोध हुआ और पत्थर बाजी भी की जिसमे कुछ पुलिस के जवान जख्मी भी हुए। इस दौरान बेस्ट को अपने मार्ग भी बदलने पर मजबूर होना पड़ा। मनपा ने पवई आईआईटी से हीरानंदानी की ओर आने वाले रास्ते को पूरी तरह बंद कर कार्रवाई की और सभी झोपड़ों को जमिदोज कर दिया गया। मनपा ने इस दौरान लगभग 100 से अधिक पुलिस का बंदोबस्त लिया था। बता दें कि पवई के जय भीम नगर इलाके में वर्षों से बसे सैकड़ों परिवारों की झुग्गियां एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गई हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद मनपा ने फुटपाथों और सार्वजनिक स्थलों पर बने अस्थायी झोपड़ों को हटाने की कार्रवाई शुरू की। अदालत ने स्पष्ट किया था कि लोकहित और सुरक्षा के मद्देनजर अवैध झुग्गियों को हटाना अनिवार्य है, जिसके चलते मनपा ने पुलिस बंदोबस्त के बीच कार्रवाई अंजाम दी। कोर्ट ने 17 अगस्त को ही कार्रवाई का आदेश दिया हुआ था।

मुंबई : ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च... मैंग्रोव वनों के मुआवजा वृक्षारोपण की जानकारी आसानी से ट्रैक कर सकते हैं

मुंबई : महाराष्ट्र के वन विभाग के मैंग्रोव सेल ने लंबे समय से प्रतीक्षित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिससे नागरिक अब राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के कारण कटाई किए गए मैंग्रोव वनों के मुआवजा वृक्षारोपण की जानकारी आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म में कुल 57 परियोजनाओं को शामिल किया गया है, जिनमें बीएमसी, मुंबई मेट्रोरेल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उक्कडड, रेलवे और अन्य राज्य एजेंसियों द्वारा संचालित परियोजनाएं शामिल हैं। प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक परियोजना द्वारा डाइवर्ज किए गए कुल वन क्षेत्र, कितने मैंग्रोव पेड़ों की कटाई की अनुमति थी, मुआवजा वृक्षारोपण की संख्या और वर्तमान में वृक्षारोपण की स्थिति को फोटो और वीडियो के साथ देखा जा सकता है। इसके अलावा, मुआवजा वृक्षारोपण की जियो-टैग्ड लोकेशन, परियोजना पर किए गए खर्च, कुल वृक्षारोपण की संख्या और उनका जीवित रहने का प्रतिशत भी इस पोर्टल पर उपलब्ध है। यह पहल पारदर्शिता बढ़ाने और आमजन को

परियोजनाओं की वास्तविक स्थिति से अवगत कराने के उद्देश्य से की गई है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यह प्लेटफॉर्म न केवल पर्यावरणीय निगरानी को आसान बनाएगा, बल्कि यह यह भी सुनिश्चित करेगा कि मैंग्रोव वनों के संरक्षण के लिए किए गए मुआवजा वृक्षारोपण की गुणवत्ता और मात्रा सही तरीके से पूरी की जा रही है। अब लोग सीधे यह देख पाएंगे कि कटाई के बदले कितने पेड़ लगाए गए और उनका वर्तमान स्वास्थ्य और जीवित रहने की दर कैसी है।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की डिजिटल पहल से जनता की भागीदारी बढ़ेगी और पर्यावरणीय संरक्षण में जवाबदेही सुनिश्चित होगी। साथ ही, सरकारी एजेंसियों द्वारा किए गए वृक्षारोपण कार्यों की निगरानी में सुधार होगा और किसी भी तरह की अनियमितताओं पर तुरंत ध्यान दिया जा सकेगा। इस प्लेटफॉर्म के जरिए आमजन मोबाइल और कंप्यूटर दोनों माध्यमों से परियोजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आवश्यकतानुसार संबंधित अधिकारियों से फीडबैक भी साझा कर सकते हैं। यह कदम महाराष्ट्र में मैंग्रोव वनों के संरक्षण और उनके सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।

मुंबई में 150 से अधिक छात्रों ने पीर मख़्दूम अली माहिम दरगाह का किया दौरा...

मुंबईः 'राष्ट्रीय कृतज्ञता सप्ताह' के तहत गुरुवार को 150 से अधिक कॉलेज छात्रों ने पीर मख़्दूम अली माहिमी दरगाह का दौरा किया। इस पहल का उद्देश्य विभिन्न धर्मों के बीच सामंजस्य बढ़ाना, सांस्कृतिक समझ को प्रोत्साहित करना और आभार की भावना पर ध्यान केंद्रित करना था। बांद्रा के आर डी नेशनल कॉलेज के छात्रों का स्वागत पीर मख़्दूम साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉ. मुदास्सिर लाम्बे और प्रबंध ट्रस्टी सुहैल खंडवानी की ओर से प्रशासक गुलामाली नाइक ने किया।

डॉ. लाम्बे ने बताया कि छात्र पांच शिक्षकों के मार्गदर्शन में विभिन्न समुदायों द्वारा प्रबंधित धार्मिक स्थलों का दौरा कर रहे हैं। ''15 अगस्त से उन्होंने सिद्धिविनायक मंदिर और एक गुरुद्वारा का दौरा किया है। यह एक वार्षिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य विभिन्न धार्मिक समूहों और उनके विश्वासों को समझना है,''उन्होंने कहा। उन्होंने यह भी बताया कि स्ट जेवियर्स कॉलेज के छात्र भी इस दरगाह का दौरा करने वाले हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों को धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता के महत्व को समझने का अवसर मिलता है।

कार्यक्रम में छात्रों ने न केवल धार्मिक स्थलों का दौरा किया बल्कि वहां के समाज सेवा और सामाजिक योगदान के पहलुओं को भी देखा। इस अनुभव से उन्हें सामाजिक जिम्मेदारी, सहिष्णुता और सह-अस्तित्व की भावना को और मजबूत करने में मदद मिली। राष्ट्रीय कृतज्ञता सप्ताह के इस पहल से युवा पीढ़ी में सहिष्णुता, सहकारिता और आभार की भावना को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। धार्मिक स्थलों का दौरा और उनके इतिहास तथा परंपराओं को जानना छात्रों के लिए सीखने का महत्वपूर्ण अनुभव साबित हो रहा है।

अस्वच्छ और गंदे माहौल में काम करने के लिए मजबूर ओल्ड सचिवालय एनेक्स बिल्डिंग में स्थित कई दफ्तर और ट्रिब्यूनल

मुंबईः ओल्ड सचिवालय एनेक्स बिल्डिंग में स्थित कई दफ्तर और ट्रिब्यूनल पिछले एक साल से अस्वच्छ और गंदे माहौल में काम करने के लिए मजबूर हैं। कार्यालयों की अनदेखी और सफाई की कमी के कारण वहां काम करने वाले कर्मचारियों और वकीलों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विशेषकर वकील इस अस्वास्थ्यकर माहौल से सबसे अधिक प्रभावित हैं। प्रैक्टिस कर रहे वकीलों का कहना है कि उन्होंने बीएमसी और पीडब्ल्यूडी दोनों को कई बार शिकायतें कीं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। महाराष्ट्र रेवेन्यू ट्रिब्यूनल में पिछले 48 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे वरिष्ठ वकील द्वारकानाथ राधाकृष्ण बनवलिकर (75) ने बताया कि ट्रिब्यूनल में काम करने की स्थिति बेहद खराब और असहनीय है।

वकील ने कहा कि कार्यालयों में गंदगी, कचरा और सफाई की कमी के कारण उनकी पेशेवर गतिविधियां प्रभावित हो

रही हैं। नोटिस बोर्ड, लॉबी और न्यायालय कक्षों में गंदगी और खराब रखरखाव का मामला लगातार बढ़ रहा है।

इसके कारण न केवल वकीलों, बल्कि आने वाले आम जनता और क्लाइंट्स को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वकीलों ने यह भी कहा कि शिकायत करने के बावजूद जिम्मेदार विभाग सक्रिय नहीं हैं। बीएमसी और पीडब्ल्यूडी द्वारा आवश्यक कदम न उठाने के कारण वकीलों और कर्मचारियों का पेशेवर माहौल प्रभावित हो रहा है। कई वरिष्ठ वकील यह भी चेतावनी दे चुके हैं कि अगर स्थिति में सुधार नहीं किया गया तो यह न्यायिक कार्यों और ट्रिब्यूनल की कार्यकुशलता पर गंभीर असर डाल सकता है। मौजूदा हालात में कार्यालयों और ट्रिब्यूनलों में साफ-सफाई और स्वच्छता बनाए रखना अत्यंत जरूरी है। वकीलों का कहना है कि उचित सफाई और रखरखाव के अभाव में उनके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस पूरे मामले में वकील और कर्मचारी दोनों ही विभागों से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ताकि ओल्ड सचिवालय एनेक्स बिल्डिंग में कामकाज सामान्य और सुरक्षित तरीके से हो सके।

मुंबई : भारी बारिश के बाद लोगों में लेप्टोस्पायरोसिस का खतरा, मनपा ने किया अलर्ट...

मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है। इस दौरान जो लोग धीमी गति से निकलने वाले पानी में चले हैं, उन्हें लेप्टोस्पायरोसिस का संक्रमण होने की संभावना रहती है। वहीं, जिन व्यक्तियों के शरीर पर घाव या खरोंच है और उसका संपर्क जमा हुए पानी या कीचड़ से हुआ है, उन्हें संक्रमण का खतरा और अधिक

होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, महानगरपालिका आयुक्त एवं प्रशासक, भूषण गगराणी, के मार्गदर्शन में सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग को जनजागृति करने और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

बारिश में लेप्टोस्पायरोसिस से बचाव उपाय

इसके साथ ही, बारिश से संबंधी बीमारियों के संदर्भ में आयोजित विशेष समीक्षा बैठक में, आयुक्त महोदय ने सभी संबंधितों को जनजागरण बढ़ाने और चिकित्सकीय उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुंबई : 23 अगस्त से 8 सितंबर तक, गणेश उत्सव के लिए कोंकण जाने वाले वाहनों और एसटी बसों को टोल से छूट...

मुंबई : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस साल गणेश उत्सव के लिए कोंकण जाने वाले गणेश भक्तों को राहत देते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। 23 अगस्त से 8 सितंबर तक, गणेश उत्सव के लिए कोंकण जाने वाले वाहनों और एसटी (राज्य परिवहन) बसों को मुंबई-बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग, मुंबई-गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग और लोक निर्माण विभाग तथा महाराष्ट्र राज्य सड़क

विकास निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाली अन्य सड़कों पर स्थित टोल प्लाजा पर टोल से छूट दी जाएगी।

संपर्क कार्याल : रोहिरा हाउस फ्लैट नो 8 दूसरा माला पाकीजा बेकरी के सामने कैडल रोड माहिम पश्चिम मुंबई ४०००१६
मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। मोबाइल नं 998777 5650, Email-editor@rokthoklekhaninews.com
www.rokthoklekaninews.com facebook@rokthoklekhani youtube@rokthoklekhani twitter@rokthoklekhani